हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 166 लखनऊ, सोमवार 09 फ़रवरी 2026 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

संघ यात्रा के 100 साल : मोहन भागवत बोले- वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो पुरस्कार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी

बीएनई

मुंबई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि यदि विनायक दामोदर सावरकर (वीर सावरकर) को भारत रत्न दिया जाता है, तो यह सम्मान खुद इस पुरस्कार की गरिमा को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि सावरकर को किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे पहले ही देशवासियों के दिलों में स्थान बना चुके हैं।

बिना किसी सम्मान के भी सावरकर जनता के दिलों पर राज करते हैं

उन्होंने कहा, मैं उस समिति का हिस्सा नहीं हूं जो इस पर फैसला करती है, लेकिन अगर किसी से मुलाकात होगी तो जरूर पूछूंगा कि इसमें देरी क्यों हो रही है। अगर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो यह पुरस्कार के लिए ही सम्मान होगा और उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। बिना किसी सम्मान के भी सावरकर जनता के दिलों पर राज करते हैं। वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग लंबे समय से राजनीतिक बहस का विषय रही है। कई संगठन और नेता उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने की मांग करते रहे हैं। वहीं, कांग्रेस पार्टी इस मांग का विरोध करती रही है। कांग्रेस का आरोप है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार को भेजी गई दया याचिकाओं के कारण सावरकर देशद्रोही थे। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिवसेना लगातार सावरकर को भारत रत्न देने के पक्ष में खड़ी रही हैं। इन दलों का कहना है कि सावरकर एक महान स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और समाज सुधारक थे और उनका योगदान देश के इतिहास में महत्वपूर्ण है। अपने संबोधन में मोहन भागवत ने आरएसएस की कार्यशैली और विचारधारा पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संघ का उद्देश्य प्रचार या आक्रामक अभियान चलाना नहीं, बल्कि समाज में अच्छे संस्कारों का निर्माण करना है। अत्यधिक प्रचार से दिखावा बढ़ता है और इससे अहंकार पैदा हो सकता है। इससे बचना जरूरी है। प्रचार वर्षा की तरह होना चाहिए, समय पर और सीमित मात्रा में।

संगठन की कार्यप्रणाली में अंग्रेजी भाषा को माध्यम नहीं बनाया जाएगा– भागवत

उन्होंने यह भी बताया कि संघ हाल के वर्षों में समाज से जुड़ने के लिए अपने संपर्क और संवाद कार्यक्रमों का विस्तार कर रहा है। भाषा के मुद्दे पर बोलते हुए आरएसएस प्रमुख ने स्पष्ट किया कि संगठन की कार्यप्रणाली में अंग्रेजी भाषा को माध्यम नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि यह भारतीय भाषा नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जहां आवश्यकता होती है, वहां अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है। हमें भारतीय लोगों के साथ मिलकर काम करना है। जहां अंग्रेजी जरूरी होगी, वहां हम उसका प्रयोग करेंगे। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि लोगों को अंग्रेजी भाषा अच्छी तरह आनी चाहिए ताकि वे उसे प्रभावी ढंग से बोल सकें। साथ ही, उन्होंने मातृभाषा के संरक्षण का जिक्र करते हुए कहा, अंग्रेजी में दक्ष होना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी मातृभाषा को भूल जाएं। उन्होंने बंगलूरू का एक उदाहरण देते हुए बताया कि दक्षिण भारत के कुछ प्रतिनिधियों को हिंदी समझने में दिक्कत हो रही थी, तब उन्होंने संवाद को प्रभावी बनाने के लिए अंग्रेजी में जवाब दिया।

जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में रखें, स्वस्थ चर्चा से कराएं प्रदेश का विकास: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में सर्वदलीय बैठक को किया संबोधित
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक
9 फरवरी सोमवार से प्रारंभ होगा विधान मंडल का बजट सत्र

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। विधान मंडल का बजट सत्र 9 फरवरी (सोमवार) से प्रारंभ होगा। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री व नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने का अनुरोध करते हुए उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं से कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में रखें और इस पर स्वस्थ चर्चा कर प्रदेश में विकास को गति प्रदान करने के लिए सरकार का सहयोग करें। विधानसभा सत्र संचालन के संबंध में विधान भवन में आयोजित इस सर्वदलीय बैठक में नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन में स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। स्वस्थ चर्चा से प्रदेश का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान होता है। जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के हित से जुड़े हर मुद्दों पर सदन में सुचारु रूप से चर्चा करनी चाहिए। सदन के संचालन में किसी प्रकार की बाधाएं न आएं, इसका ध्यान सभी सदस्यों को रखना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी सदन के सुचारु संचालन के लिए सभी सदस्यों का सहयोग मांगा। बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद, कांग्रेस की आराधना मिश्रा 'मोना', निषाद पार्टी के रमेश सिंह, लोकदल के राजपाल बालियान, अपना दल के रामनिवास वर्मा आदि मौजूद रहे।

संक्षिप्त समाचार

कर्नाटक: विजयपुरा में बड़ा हादसा, प्राइवेट जेट हुआ क्रैश, 2 लोग घायल

एजेंसी

विजयपुरा। कर्नाटक के विजयपुर जिले में रविवार दोपहर एक छोटा निजी विमान एक खुले मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि, विमान में सवार पायलट सहित दोनों लोग दुर्घटना से पहले ही उससे बाहर निकलने में सफल रहे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दो सीट वाला विमान विजयपुर के बाबलेश्वर तालुक के मंगलुरु गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने कहा कि विमान में सवार दोनों व्यक्ति हादसे से पहले उससे बाहर निकलने में सफल रहे। सूत्रों के मुताबिक, हादसे में विमान के तीन टुकड़े हो गए। विमान में सवार पायलट सहित दोनों लोगों को चोटें आई हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। प्रशिक्षण विमान ने कलबुर्गी से बेलगावी के लिए उड़ान भरी थी। घटना के सिलसिले में और जानकारी की प्रतीक्षा है।

आजाद हिंद फौज के वरिष्ठ सेनानी जयराज राजा राव से मिले पीएम मोदी, नेताजी को दी श्रद्धांजलि

एजेंसी

कुआलालंपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलयेशिया की अपनी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान आजाद हिंद फौज (इंडियन नेशनल आर्मी) के पूर्व सैनिक से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में ईएनए की ऐतिहासिक भूमिका और दक्षिण–पूर्व एशिया में बसे भारतीय समुदाय के बीच उसकी स्थायी विरासत को रेखांकित किया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने ईएनए के वरिष्ठ सेनानी जयराज राजा राव से भेंट की और इस मुलाकात को अत्यंत प्रेरक बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि जयराज राजा राव का जीवन अदम्य साहस और बलिदान से भरा है, और उनके अनुभव सुनना बेहद प्रेरणादायक रहा। नेताजी को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि वहीं, जयराज राजा राव ने भी प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात को अपने जीवन का यादगार पल बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्रता आंदोलन और आजादी के बाद भारत की प्रगति जैसे विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना भी की।

विकसित भारत के लक्ष्य को प्राथमिकता, वित्त मंत्री बोलीं- लोकलुभावन एलान नहीं सुधारों पर फोकस

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट 2026–27 को लेकर कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि बार–बार बदलती नीतियों से पैदा होने वाली अनिश्चितता को खत्म करना ही इस बार के बजट की असली सोच है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसी पिंग–पोंग से बचने की सोच ही केंद्रीय बजट 2026–27 की सबसे बड़ी नींव है। उन्होंने बताया कि बजट में तात्कालिक लाभ के बजाय नीति स्थिरता, दीर्घकालिक योजना और 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में सीतारमण ने कहा कि यह बजट नए पांच साल के वित्तीय चक्र का पहला बजट है और 21वीं सदी की दूसरी तिमाही का पहला बजट है। इस बजट में किसी तरह के लोकलुभावन एलान की बजाय पूंजीगत खर्च (कैपिटल एक्सपेंडिचर), इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और संरचनात्मक सुधारों को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही सरकार ने राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। नीति में स्थिरता जनता का जनादेश उन्होंने बताया कि लोगों को स्थिरता चाहिए थी, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार चुना। यह स्थिरता नीतियों में भी साफ दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की तीसरी जीत इस बात का संकेत है कि जनता नीति और राजनीतिक स्थिरता चाहती है, जिसे सरकार विकास की बुनियाद मानती है। 'पॉलिसी पिंग–पोंग' से बचने की सोच वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री बार–बार इस बात पर जोर देते हैं कि एक बार कोई नीति तय हो जाए, तो उसे लगातार और मजबूती से लागू किया जाना चाहिए, न कि बार–बार दिशा बदली जाए। यही सोच बजट की नीतियों में भी झलकती है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट को केवल एक साल के खर्च के रूप में नहीं देखना चाहिए। हम 2047 तक और उससे आगे, 2050 तक की तैयारी कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत को 'विकसित राष्ट्र' बनाया जाए और अगले 25 वर्षों की चुनौतियों के लिए देश को तैयार किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश सरकार की बड़ी सफलता इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च इस सरकार की बड़ी सफलता रही है।

> बार-बार बदलती नीतियों से पैदा होने वाली अनिश्चितता को खत्म करना ही इस बार के बजट की असली सोच है। इसमें तुरंत लाभ के बजाय नीति स्थिरता, दीर्घकालिक योजना और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है।
>
> निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री

झूला संचालक और कर्मचारियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज

बीएनई

फरीदाबाद। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में झूला गिरने की घटना में फरीदाबाद पुलिस ने सूरजकुंड पुलिस स्टेशन में झूला संचालक और उसके कर्मचारियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में मुख्य आरोपी हिमाचल फन केयर के मालिक मोहम्मद शाकिर हैं, जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के टोका नांगला गांव के निवासी है। शनिवार शाम को वे ही उस विशाल झूले का संचालन कर रहे थे जो बीच हवा में टूटकर गिर गया, जिससे एक पुलिस निरीक्षक की मौत हो गई। पुलिस ने डीसीपी क्राइम मुकेश कुमार की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया, जो एनआईटी की क्राइम ब्रांच के प्रभारी हैं और सूरजकुंड पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर संजय कुमार इस दल के अन्य सदस्य हैं। यह दल जिम्मेदारी, सुरक्षा अनुपालन और संभावित लापरवाही सहित सभी पहलुओं की जांच करेगा। शिकायतकर्ता एएसआई सनी ने बताया कि घटना के समय वह अपने प्रभारी इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मेले में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि शाम करीब 6 बजे कुछ लोग सुनामी झूले पर झूल रहे थे, तभी अचानक वह एक तरफ से टूट गया। इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद और उनके साथी कर्मचारी लोगों को बचाने के लिए दौड़े। जब वे ऐसा कर रहे थे, तभी झूला दूसरी तरफ से भी टूट गया और उन पर गिर पड़ा। इस घटना में इंस्पेक्टर प्रसाद, अन्य पुलिसकर्मियों और लोगों को गंभीर चोटें आईं।

सभी को अलग–अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हालांकि, इंस्पेक्टर प्रसाद ने दम तोड़ दिया। एएसआई सनी ने अपनी शिकायत में आगे कहा कि हमारे इंस्पेक्टर की मौत हिमाचल फन फेयर कंपनी के मालिक मोहम्मद शाकिर और उनके कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर लोगों की जान को खतरे में डालने के कारण हुई, क्योंकि उन्होंने सूरजकुंड मेले में लगे झूलों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया।

सरयू नदी में उतराता मिला एसआई का शव, पांच फरवरी से थे लापता, बस्ती जिले में प्रभारी थानाध्यक्ष थे

बीएनई

अयोध्या। यूपी के अयोध्या में रविवार की देर शाम अयोध्या कोतवाली क्षेत्र और बस्ती जिले की सीमा पर सरयू नदी में एक उप निरीक्षक का शव उतारता हुआ मिला। इनकी पहचान बस्ती जिले के परशरामपुर थाने में तैनात एसआई अजय गौड़ के रूप में हुई। यह पांच फरवरी से लापता थे। तब से तलाश की जा रही थी। नाविकों ने नयाघाट से दशरथ समाधि स्थल की ओर निर्माणाधीन हाईवे के पास नदी में शव उतराता देखा। नाविक की सूचना पर कोतवाली और जल पुलिस की टीम पहुंची। रेस्क्यू करके शव को तिहुरा माझा के पास से बाहर निकलवाया गया। पहचान होने के बाद पुलिस ने बस्ती जिले की पुलिस को भी सूचित किया। एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी, कोतवाल पंकज सिंह, दर्शन नगर चौकी इंचार्ज बृजभूषण पाठक आदि मौके पर गए और छानबीन शुरू की। बताया गया कि अजय गौड़ वर्तमान में प्रभारी थानाध्यक्ष थे। संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे। वह मूलरूप से देवरिया के रहने वाले बताए गए हैं। एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि घटनास्थल को लेकर अभी संदेह है। यदि बस्ती जिले की सीमा में शव मिला होगा तो वहां की पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। अन्यथा जिले की पुलिस पोस्टमार्टम और पंचनामा की कार्रवाई के लिए तैयार है। मामले की छानबीन की जा रही है।

भारत–फ्रांस के बीच SCALP क्रूज मिसाइलों की बड़ी डील संभव, करीब 3200 करोड़ का सौदा जल्द

बीएनई

नई दिल्ली। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करते हुए स्काल्प क्रूज मिसाइलों की बड़ी डील पर बातचीत चल रही है। यह सौदा करीब 3200 करोड़ रुपये (300 मिलियन यूरो) का हो सकता है, जिसे जल्द अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक, भारतीय वायुसेना (आईएएफ) फ्रांस से स्काल्प क्रूज मिसाइलों की बड़ी खेप खरीदने की तैयारी में है। इन मिसाइलों ने बीते वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी मारक क्षमता साबित की थी।

राफेल बनेगा IAF की रीढ़

भारतीय वायुसेना अपने राफेल बेड़े के साथ स्काल्प क्रूज मिसाइलों को तैनात करेगी। इसके साथ ही आईएएफ मेटियोर एयर–टू–एयर मिसाइलों की भी बड़ी खरीद की प्रक्रिया में है। स्काल्प और मेटियोर मिसाइलों को भारतीय नौसेना के लिए ऑर्डर किए गए 26 राफेल मरीन विमानों में भी शामिल किया जाएगा, जिनकी डिलीवरी अगले 3–4 वर्षों में होने की उम्मीद है।

ऑपरेशन सिंदूर में राफेल विमानों के शानदार प्रदर्शन और क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा खतरे को देखते हुए, भारतीय वायुसेना 114 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की योजना बना रही है। यह प्रस्ताव जल्द ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से मंजूरी पा सकता है। आने वाले 10–15 वर्षों में भारतीय वायुसेना के पास करीब 200 राफेल विमान हो सकते हैं, जिससे यह फाइटर जेट वायुसेना की मुख्य ताकत बन जाएगा।

मैक्रों के भारत दौरे से पहले बन सकती है सहमति

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के 18 से 20 फरवरी के प्रस्तावित भारत दौरे से पहले रक्षा क्षेत्र से जुड़े एक अहम निर्णय पर अंतिम सहमति बनने की संभावना है। मैक्रों इस दौरान भारत में आयोजित होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में भाग लेने के लिए आ रहे हैं और माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को नई दिशा मिल सकती है।

ऑपरेशन सिंदूर में दिखीं थी SCALP की ताकत

भारतीय वायुसेना ने राफेल लड़ाकू विमानों से स्काल्प और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को दागकर पाकिस्तान के मुरीदके और बहावलपुर में स्थित जैश–ए–मोहम्मद और लश्कर–ए–तैयबा के आतंकी ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था।

आतंकवाद पर भारत का संदेश बिल्कुल साफ, कोई दोहरा मापदंड और समझौता नहीं, मलयेशिया में बोले पीएम मोदी

एजेंसी

कुआलालंपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रविवार को मलयेशिया की प्रशासनिक राजधानी पुत्रजाया के पर्दाना पुत्र भवन में औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान मलयेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी के मलयेशिया दौरे का दूसरा दिन वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलयेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने दोनों देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। बता दें कि, आज पीएम मोदी के मलयेशिया दौरे का दूसरा दिन है। यह उनका 2026 का पहला विदेश दौरा है। मलयेशियाई पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता वहीं इसके बाद पीएम मोदी और मलयेशियाई पीएम ने द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा– भारत–मलयेशिया की साझेदारी ऐतिहासिक है और दोनों देशों में सहयोग लगातार बढ़ा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मलयेशियाई प्रधानमंत्री और वहां की सरकार का दिल से धन्यवाद करते हुए कहा कि जिस तरह उनका और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया गया, वह हमेशा यादगार रहेगा। उन्होंने कहा कि पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर मलयेशियाई जीवन और संस्कृति को जिस खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया, उसने इस यात्रा को खास बना दिया। भारत और मलयेशिया के रिश्ते बेहद अच्छे वहीं मलयेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और मलयेशिया के बीच रिश्ते बेहद अच्छे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं, जिन पर दोनों पक्षों की टीमें मिलकर काम करेंगी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में हर क्षेत्र में सहयोग और बढ़ेगा। अनवर इब्राहिम ने यह भी कहा कि यह यात्रा उनके लिए व्यक्तिगत रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने मलयेशिया को आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए दी बधाई इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह भारत–मलयेशिया दोस्ती की ऊंचाई और गहराई दोनों को महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के रूप में यह उनका मलयेशिया का तीसरा दौरा है और अनवर इब्राहिम के कार्यकाल में उनसे यह चौथी मुलाकात है। उन्होंने कहा कि यही बात दोनों देशों के रिश्तों की गति और मजबूती को दिखाती है। हाल के वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों ने जिस रफ्तार और गहराई को छुआ है, वह वाकई प्रेरणादायक है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि आज भारत और मलयेशिया के बीच सहयोग हर क्षेत्र में बढ़ रहा है– चाहे वह कृषि हो, विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा या सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक क्षेत्र हों। दोनों देश कौशल विकास और क्षमता निर्माण में भी अहम साझेदार हैं। इसके अलावा रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने मलयेशिया को आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए बधाई दी और कहा कि मलयेशिया के सहयोग से भारत–आसियान रिश्ते और गहरे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत–मलयेशिया संबंधों की असली ताकत लोगों के बीच के रिश्तों में है। मलयेशिया में रहने वाले लगभग 30 लाख भारतीय मूल के नागरिक दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु की तरह हैं। शनिवार को भारतीयों से मिले पीएम मोदी इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कुआलालंपुर पहुंचने पर भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच डिजिटल सहयोग में तेजी आ रही है और भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) जल्द ही मलयेशिया में शुरू की जाएगी।

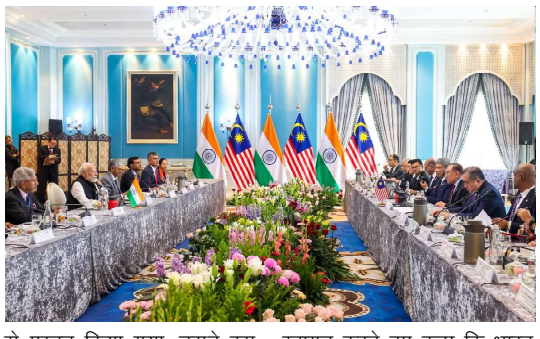

संपादकीय

मोदी और कार्नी : एक नए ग्लोबल ऑर्डर के रचयिता

इकोनॉमिक नैशनलिज्म के फिर से उभरने से दुनिया की राजनीति में पुराने रिवाज हिल गए हैं और नियमों पर आधारित इंटरनैशनल ऑर्डर में भरोसा डगमगा गया है। यह सबसे साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ वॉर के दौरान दिखा, जिसमें न सिर्फ दुश्मनों को, बल्कि साथियों को भी टारगेट किया गया। भारत, जो कभी अमरीका की इंडो–पैसिफिक पॉलिसी में एक पसंदीदा पार्टनर था और कनाडा, जो एक अच्छा पड़ोसी और समय की कसौटी पर खरा उतरा दोस्त था, दोनों टैरिफ का शिकार हुए। मैसेज साफ था–स्वार्थ से चलने वाली दुनिया में, भरोसेमंद पार्टनर भी अब स्थिरता को हल्के में नहीं ले सकते।इसने मध्यम और उभरते देशों को ग्लोबल सिस्टम में अपनी जगह पर फिर से सोचने पर मजबूर किया। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और मार्क कार्नी के बताए गए विचार खास अहमियत रखते हैं। साथ मिलकर, अपने कामों और अपने आइडिया के जरिए, वे सहयोग और नियमों के सम्मान पर आध ारित एक बैलेंस्ड ग्लोबल ऑर्डर की ओर इशारा करते हैं। दावोस में कार्नी ने समाज के उस हिस्से की आवाज बनकर बात की, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है–डिवैल्ड और डिवैल्पिंग दुनिया की 'मिडल पावर्स'। उनकी स्पीच ने बड़े पावर स्ट्रगल और आर्थिक संकटों में फंसे देशों की नाराजगी को साफ तौर पर दिखाया। इससे भी जरूरी बात यह है कि उन्होंने दुनिया को एक नई वोकैबुलरी दी, जिसने डिवैल्ड और डिवैल्पिंग देशों के बीच बढ़ते गैप को कम करने और एक सांझा भविष्य की रक्षा करने की सांझी जिम्मेदारी पर जोर दिया। कार्नी का संदेश साफ था–रूल्स–बेस्ड ऑर्डर पर दबाव है लेकिन यह न तो आऊटडेटेड है और न ही रिप्लेसेबल। इसे रिफ्रेश करने की जरूरत है, छोडने की नहीं। इसी ग्लोबल इनस्टेबिलिटी के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी की अप्रोच कम शोर वाली रही लेकिन कम असरदार नहीं। बयानबाजी की बजाय, भारत ने रणनीतिक आर्थिक राजनीति पर फोकस किया। ट्रेड वॉर के एक दौर के बाद, नई दिल्ली ने न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन जैसे पार्टनर्स के साथ उच्च गुणवत्तापूर्ण फ्री ट्रेड एग्रीमैंट्स को तेजी से आगे बढ़ाया है। ये एग्रीमैंट इंटरनैशनल ट्रेड में बहुत जरूरी स्थिरता देते हैं, खुलेपन के लिए भारत की कमिटमैंट दिखाते हैं और इसे ग्लोबल कैपिटल के लिए एक पसंदीदा मार्केट और गंतव्य बनाते हैं।

सप्लाई चेन में रुकावटों और अस्थिर कैपिटल फ्लो के समय में, भारत स्थिरता का एक मजबूत पिल्लर बनकर उभरा है। इन दोनों अप्रोच का कॉम्बिनेशन–कार्नी की आइडियोलॉजिकल दिशा और मोदी का प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस–एक मजबूत कम्युनिटी के लिए स्टेज तैयार करता है। मार्च में कार्नी का भारत दौरा, जिसके दौरान एक बड़ी एनर्जी डील होने की संभावना है और कॉम्प्रिहैंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमैंट (सी.ई.पी.ए.) पर बातचीत चल रही है, इस कॉम्बिनेशन को दिखाता है। एक स्ट्रक्चर्ड इंडिया–कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमैंट से दोनों देशों को फायदा होगा–एनर्जी को–ऑप्रेशन मजबूत होगा, सप्लाई चेन में डायवर्सिटी आएगी और इन्वैस्टमैंट फ्लो बढ़ेगा। मोटे तौर पर, भारत और कनाडा दुनिया में स्थिरता के केंद्र बन सकते हैं। दोनों ही प्लूरलिस्टिक डैमोक्रेसी हैं, ग्लोबलाइजेशन के लाभार्थी हैं लेकिन इसकी इनइक्वालिटीज के बारे में भी अच्छी तरह जानते हैं। इकोनॉमिकली, डिप्लोमैटिकली और मोरली एक साथ आगे बढ़कर, ये दोनों देश रूल्स–बेस्ड ऑर्डर में भरोसा बनाए रख सकते हैं–एक ऐसा सिस्टम, जो सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए काम करे। ग्लोबल लीडरशिप अब सिर्फ दबदबे से तय नहीं होती। इसे पुल बनाने, भरोसा फिर से बनाने और तब स्थिरता देने से तय किया जाता है, जब दूसरे देश जीरो–सम सोच की ओर मुड़ जाते हैं। अलग–अलग तरीकों से, मोदी और कार्नी एक ही काम कर रहे हैं–चुपचाप एक नए ग्लोबल ऑर्डर का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं।

जब संसद ही मर्यादा तोड़े, तो आचार-संहिता किसके लिए?

–डॉ० प्रियंका सौरभ

आज भारतीय संसद की कार्यवाही ने लोकतंत्र की उस बुनियादी शर्त पर गहरे प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं, जिसे हम समानता, गरिमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। संसद केवल कानून बनाने की जगह नहीं होती, बल्कि वह वह मंच होती है जहाँ लोकतंत्र की आत्मा बोलती है। लेकिन जब उसी मंच पर निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी बात निर्बाध रूप से नहीं रख पा रहे हों, तो यह केवल संसदीय अव्यवस्था नहीं रह जाती, बल्कि लोकतांत्रिक चेतना के क्षरण का संकेत बन जाती है। यह स्थिति इसलिए भी अधिक चिंताजनक है क्योंकि संसद वह संस्था है, जिससे पूरे समाज को दिशा मिलती है। यदि यहाँ शोर, व्यवधान, व्यक्तिगत हमले और लक्षित अपमान सामान्य होते जा रहे हैं, तो यह संदेश केवल संसद तक सीमित नहीं रहताकृयह पूरे समाज में असहिष्णुता और अराजकता को वैधता देता है। यह विडंबना ही है कि जिस देश ने अपने संविधान के माध्यम से जाति, वर्ग और भेदभाव से मुक्ति का सपना देखा था, उसी देश की संसद में आज भी व्यक्ति की पहचान उसके पद से पहले उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि से तय होती दिखाई देती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या प्रधानमंत्री का धन्यवाद प्रस्तावकृयदि इन संवैधानिक प्रक्रियाओं को भी शोर, व्यवधान और लक्षित अपमान के बीच पूरा न किया जा सके, तो सवाल केवल राजनीतिक शिष्टाचार का नहीं रहता, बल्कि संस्थागत मर्यादा का बन जाता है। संविधान ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे पदों को किसी जाति, वर्ग या समुदाय से ऊपर रखा है। ये पद संविधान की संप्रभुता के प्रतीक हैं। लेकिन जब इन पदों पर बैठे व्यक्तियों को भी उनकी सामाजिक पहचान के चश्मे से देखा जाता है, तो यह उस गहरी जातिगत मानसिकता को उजागर करता है, जो आज भी हमारे लोकतंत्र के भीतर जीवित है। संसद में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार हैकृबल्कि लोकतंत्र में यह उसका कर्तव्य है। लेकिन सवालों का स्वर, भाषा और उद्देश्य भी लोकतांत्रिक मर्यादा के भीतर होना चाहिए। जब प्रश्न नीति, प्रशासन और जनहित की जगह व्यक्तिगत

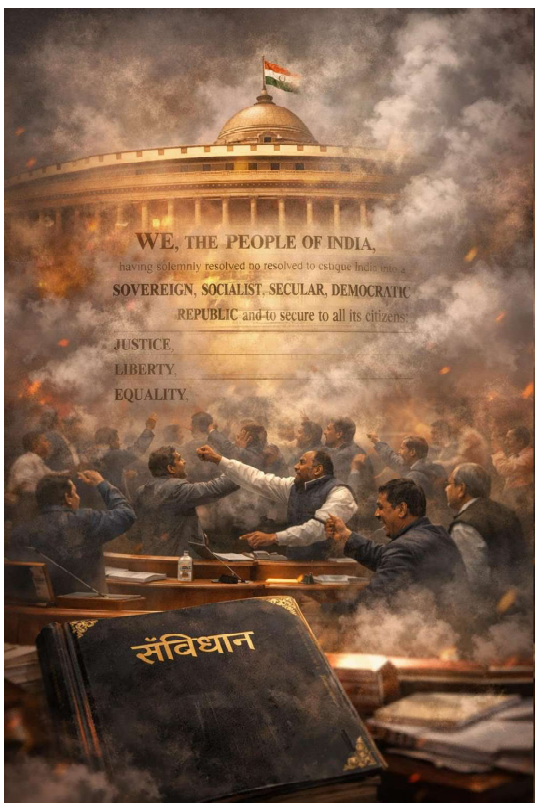

पहचान, सामाजिक वर्ग या जातिगत संकेतों की ओर मुड़ने लगें, तो यह विमर्श नहीं, बल्कि विभाजन की राजनीति बन जाती है। यह प्रवृत्ति न केवल संसद की गरिमा को ठेस पहुँचाती है, बल्कि समाज को भी वही संदेश देती है कि सत्ता के शीर्ष पर पहुँचने के बाद भी व्यक्ति जातिगत खाँचों से मुक्त नहीं हो सकता। इसका असर केवल राजनीतिक नहीं होता, इसका सामाजिक प्रभाव भी गहरा होता हैकृयह उन करोड़ों लोगों को निराश करता है जो लोकतंत्र को सामाजिक न्याय का माध्यम मानते हैं। एक सौ चालीस करोड़ की आबादी वाले देश में संसद केवल कानून बनाने की जगह नहीं है; वह लोकतंत्र का नैतिक केंद्र है। यही वह स्थान है जहाँ असहमति को सम्मान मिलना चाहिए, जहाँ बहस होनी चाहिए लेकिन अपमान नहीं, जहाँ टकराव हो लेकिन हिंसक भाषा नहीं। यदि उसी केंद्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सुरक्षा, सम्मान और अभिव्यक्ति सुनिश्चित नहीं हो पा रही, तो यह तंत्र की गंभीर विफलता है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या संसद के भीतर अनुशासन केवल कागज़ों तक सीमित रह गया है? क्या सदन की कार्यवाही बाधित करना, योजनाबद्ध शोर मचाना और संवैधानिक प्रक्रियाओं को रोकना अब राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन चुका है? और यदि ऐसा है, तो क्या इसके लिए कोई स्पष्ट और कठोर जवाबदेही तय की जाएगी? आज विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और सार्वजनिक संस्थानों के लिए आचार–संहिताएँ बनाई जाती हैंकृछात्रों और शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे मर्यादा और अनुशासन में रहें। लेकिन क्या यह विडंबना नहीं है कि संसद, जो इन नियमों को बनाने वाली संस्था है, स्वयं अनुशासनहीनता का उदाहरण बनती जा रही है? क्या संसद के लिए भी किसी सख़्त आचार–संहिता की आवश्यकता नहीं है, जो केवल काग़ज़ पर नहीं, व्यवहार में लागू हो? यह बहस किसी एक पद, व्यक्ति या राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। यह उस मानसिकता का प्रश्न है, जो आज भी व्यक्ति को उसकी संवैधानिक भूमिका से पहले उसकी जाति में बाँधकर देखती है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रीकृदोनों पद संविधान से शक्ति पाते हैं न कि किसी सामाजिक श्रेणी से। फिर भी, जब सदन के भीतर और बाहर उन्हें उसी पुरानी दृष्टि से देखा जाता है, तो यह लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा आघात है। हम अक्सर गर्व से कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र केवल संख्या से बड़ा नहीं होता, उसकी गुणवत्ता भी मायने रखती है। यदि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच पर ही समानता और सम्मान सुनिश्चित नहीं हो पा रहे, तो यह आत्ममंथन का समय है। देश ने बीते दशकों में विकास, तकनीक और वैश्विक पहचान के अनेक पड़ाव पार किए हैं। हम अंतरिक्ष में पहुँच गए, डिजिटल अर्थव्यवस्था बना ली, वैश्विक मंचों पर अपनी आवाज़ बुलंद की। लेकिन सामाजिक समानता की कसौटी पर आज भी हम बार–बार फिसलते दिखाई देते हैं। जाति, पहचान और पूर्वाग्रह आज भी हमारे सार्वजनिक जीवन को नियंत्रित करते हैं। यदि संसद स्वयं इस सोच से मुक्त नहीं हो पाती, तो समाज से परिवर्तन की अपेक्षा करना व्यर्थ है। संसद को केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं, बल्कि उदाहरण प्रस्तुत करने वाली संस्था बनना होगा। यहाँ जो आचरण होगा, वही समाज में आदर्श माना जाएगा। इसलिए यह समय है कि संसद की गरिमा, समानता और कार्यवाही की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट, पारदर्शी और कठोर नियमों पर गंभीर विचार किया जाए। ऐसे नियम जो सत्ता पक्ष और विपक्षकृ दोनों पर समान रूप से लागू हों। ऐसे नियम जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाएँ नहीं, लेकिन अराजकता को भी अनुमति न दें। लोकतंत्र की मजबूती शोर से नहीं, संवाद से आती है; अवरोध से नहीं, असहमति के सम्मान से आती है। संसद को फिर से वही स्थान बनना होगा, जहाँ विचार टकराएँ, लेकिन व्यक्ति अपमानित न हो; जहाँ सत्ता और विपक्ष आमने–सामने हों, लेकिन संविधान सर्वोपरि रहे। यदि संसद ही मर्यादा तोड़ेगी, तो देश से मर्यादा की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? यही प्रश्न आज भारतीय लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। तभी लोकतंत्र अपनी वास्तविक अर्थवत्ता में जीवित रह पाएगा।

टैरिफ वार छेड़ने वाले ट्रम्प आखिर भारत के सामने कैसे नतमस्तक हुए

रवि शंकर

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूरोपीय संघ और भारत ने मुक्त व्यापार समझौता करने की घोषणा की है। इसे दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक समझौतों में से एक कहा जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस समझौते की सबसे बड़ी वजह मौजूदा वैश्विक राजनीति है, जिसमें अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कारोबार का इस्तेमाल अन्य देशों पर दबाव बनाने के लिए एक कूटनीतिक हथियार की तरह कर रहे हैं। अमरीका की इसी आक्रामकता का जवाब देने के लिए यूरोपीय संघ और भारत तेजी से मुक्त व्यापार समझौते की तरफ बढ़े हैं लेकिन इसके प्रभावी होने में अभी लंबा वक्त लग सकता है क्योंकि इसे कानूनी रूप देने के लिए यूरोपीय संघ की पाध्लयामैंट और यूरोपीय परिषद में पारित करवाना है। बहरहाल, भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमैंट केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि यह बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन और भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं का भी संकेत देता है। यह डील ऐसे समय में सामने आई है, जब अमरीका और भारत के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ा हुआ है और अमरीका भारतीय निर्यात पर भारी टैरिफ लागू कर चुका है। लेकिन यूरोपीय संघ और भारत के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते ने अमरीका को आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर असहज कर दिया। यही वजह है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को आखिरकार झुकना पड़ा और भारतीय सामानों पर लगने वाला टैरिफ 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करना पड़ा। यह फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला रहा क्योंकि इससे पहले तक बातचीत बेनतीजा रही थी और अमरीका लगातार भारत पर दबाव बना रहा था। यह समझौता सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि दबाव, मजबूरी और रणनीतिक बदलाव की भी मिसाल है। ट्रम्प के इस फैसले के पीछे भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई बड़ी ट्रेड डील अहम वजह बनी। इस डील से भारत की ताकत बातचीत में बढ़ गई और अमरीका को यह डर सताने लगा कि कहीं वह पीछे न छूट जाए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले ही भारत–ई.यू. डील को विकास, निवेश और रणनीतिक सांझेदारी के लिए बड़ा कदम बताया था। गौरतलब है कि दुनिया को जब डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ वॉर झकझोर रही थी, तब भारत ने सीधे टकराव की बजाय कूटनीति का रास्ता चुना। भारत ने अपने उत्पादों के लिए वैकल्पिक बाजार तलाशे। यूरोपियन यूनियन के साथ ऐतिहासिक डील, ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ समझौतों ने अमरीका पर दबाव बढ़ा दिया। ट्रम्प को समझ आ गया कि भारत के खिलाफ टैरिफ युद्ध छेडना एक बड़ी गलती थी। यह समझौता सिर्फ कारोबार तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसके प्रभाव वैश्विक राजनीति पर भी होंगे, खासकर अमरीकी आक्रामक कारोबार नीति पर। अमरीका लंबे समय से भारत जैसे बड़े बाजार के साथ एक बड़ी ट्रेड डील करना चाहता था, ताकि वह भारतीय बाजार से अधिकतम लाभ उठा सके। ऐसे में भारत और ई.यू. के बीच हुई डील अमरीका के लिए एक रणनीतिक झटका है, क्योंकि इससे अमरीका–भारत ट्रेड एग्रीमैंट की संभावनाएं कमजोर होती दिख रही थीं। यूरोपीय संघ के साथ समझौता आगे बढ़ाने का भारत का फैसला उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता को दर्शाता है। इसी कदम ने संभवतरू अमरीका को यह संकेत दिया कि अगर वह भारत के साथ समझौता जल्दी नहीं करता, तो उसे रणनीतिक और आर्थिक नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि ट्रम्प को अपनी रणनीति भारत के खिलाफ बदलनी पड़ी।भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों, जैसे कि रूसी कच्चा तेल पर समझौता किए बिना भी वैश्विक शक्तियों के साथ बराबरी के स्तर पर व्यापार कर सकता है। साफ है, भारत ने अमरीका के साथ सीधे टकराव की बजाय धैर्य, कूटनीति और वैकल्पिक बाजारों की रणनीति अपनाई। नतीजा यह हुआ कि टैरिफ वॉर में भारत मजबूती से खड़ा रहा और आखिरकार झुकना अमरीका को पड़ा। बहरहाल, यह समझौता भारत के लिए कई महत्वपूर्ण सबक और चुनौतियां भी पेश करता है। यह दर्शाता है कि प्रमुख ग्लोबल अर्थव्यवस्थाओं के बीच संरक्षणवाद बढ़ रहा है। देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए टैरिफ और व्यापार धमकियों का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं कर रहे। भारत को अपनी निर्यात रणनीतियों और व्यापार समझौतों को इस बदलते सीन के अनुरूप ढालना होगा। अगर अमरीका और ई.यू. जैसे बड़े ब्लॉक द्विपक्षीय समझौतों पर फोकस करते हैं।

राशिफल

मेष :– किसी पुराने संबंध के प्रति विशेष निकटता की अनुभूति करेंगे। ग्रहों की अनुकूलता से अवरोधित कार्य हल होने के आसार हैं। भौतिक आकांक्षाएं सार्थकता हेतु मन को उद्वेलित करेंगी। घर में खुशहाली रहेगी।

बृषभ :– जीवन में सही लक्ष्य व सुदृढ़ता को सुनिश्चित करें तभी जीवन में सही प्रगति कर सकते हैं। बीते हुए दिनों को याद कर भाव–विभोर हो सकते हैं। व्यग्रता महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एकाग्रता का अभाव पैदा करेगी।

मिथुनः– किसी भी प्रयास में आर्थिक अभाव अवरोधक होगा। साहस व बुद्धिमता से पुरानी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सुख की अनुभूति करेंगे। निकट संबंधों में मधुर संवाद से अपनी सुन्दर छबि बनावें।

कर्क :– किसी नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी। पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट संभव। भविष्य के प्रति मन में चिन्ताएं उत्पन्न होंगी। वर्तमान कार्य से मन में असन्तुष्टि उत्पन्न होगी।

सिंह :– किसी बड़े आयोजन हेतु समुचित साधन व्यवस्था के लिए मन प्रयत्नशील होगा। शासन–सत्ता में व्यस्तता बढ़ेगी। मन आर्थिक सुदृढ़ता हेतु चिंतित होगा। परिजनों के सुख–दुख के प्रति मन में चिंता उत्पन्न होगी।

कन्या :– बुद्धिमत्ता व परिश्रम का मिला–जुला संजोग का भरपूर लाभ उठाएंगे। आर्थिक क्षेत्र में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। सफलताएं आन्तरिक क्षमताओं का एहसास कराएंगी। संतान संबंधी दायित्वों की पूर्ति होगी।

तुला :– कोई छोटी बात भी परिवार में तनाव का कारण बन सकता है। महत्वपूर्ण प्रयत्न की सार्थकता नये उत्साह का संचार करेगा। सामाजिक गतिविधियों में क्रियाशीलता बढ़ेगी। भावनात्मक अभिव्यक्ति से संबंध मधुर होंगे।

वृश्चिक :– हर घटना से आपको सीख लेने की जरुरत है। नये क्षेत्र में निवेश से पूर्वबुद्धिजीवियो से विचार–विमर्श करें। भविष्य के प्रति निराशा जनक विचारों को मन पर हावी न होने दें। नये व्यावसायिक यात्राओं का योग है।

धनु :– कुछ महत्वपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति होने के आसार बनेंगे। सामान्य दिनचर्या के साथ बीत रहे जीवन में उत्साह अभाव रहेगा। विषम स्थितियों के मध्य परिश्रम व लगन से प्रगति की ओर अग्रसर होंगे।

मकर :– किसी कार्य को छोटा–बड़ा समझने के बजाए अपने कर्त्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करें। छोटी–छोटी पारिवारिक बातों को बाहरी लोगों से न कहें। भावना से उद्वेलित मन संबंधों के सुख–दुख के प्रति चिंतित होगा।

कुंभ :– महत्वाकांक्षी अभिलाषाएं मन में असन्तुष्टि पैदा करेंगी। तामसिक विचारों को मन से दूर रखें। विपरीतलिंगी संबंधों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति में व्यय अपेक्षित है।

मीन :– सामाजिक सक्रियता से मान–प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राजनीतिज्ञों को ग्रहों की अनुकूलता का लाभ मिलेगा। पारिवारिक दायित्वों की चिंता उत्पन्न होगी। अपने स्वास्य के प्रति लानपरवाही न बरतें। आलस्य कतई न करें।

डराने लगी है ऑनलाइन गेमिंग की लत एवं आभासी दुनिया

–ललित गर्ग

ऑनलाइन गेमिंग की लत एवं आभासी दुनिया कितनी भयावह एवं घातक हो सकती है, इसकी एक ही दिन में दो अलग–अलग जगह घटी घटनाओं ने न केवल झकझोरा है, बल्कि यह हमारे समय, हमारी सामाजिक संरचना और हमारी सामूहिक असावधानी पर लगा हुआ एक गहरा प्रश्नचिह्न बना है। धीरे–धीरे किशोरवय को अपने चपेट में लेने वाली यह प्रवृत्ति कितनी हृदयविदारक हो सकती है, उसका उदाहरण बुधवार को घटी ये दो भयावह घटनाएं हैं। एक हृदयविदारक घटना में गाजियाबाद की तीन अल्पवयस्क बहनों ने नौवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 12, 14 और 16 साल की तीन सुकोमल बहनें असमय काल–कवलित हो गईं। ऑनलाइन कोरियन गेम की दीवानी बहनें कोरिया में जाकर बसने और वहीं नया जीवन शुरू करने का सपना देखती थीं। घर वालों ने जब उनकी ऑनलाइन सनक से परेशान होकर उनसे मोबाइल छीन लिए, तो वे तनाव व अवसाद में घिर गईं। फिर तीनों बहनों ने नौवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। ऐसी ही घटना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी घटी जहां एक पंद्रह वर्षीय किशोर ने ऑनलाइन गेम के अपने एक विदेशी साथी के बिछुड़ने के गम में घर में आत्महत्या कर ली। किशोर दसवीं का छात्र था। इन घटनाओं ने समाज को स्तब्ध ही नहीं किया, बल्कि भीतर तक गहरा घाव दिया है। यह कोई आकस्मिक या अलग–थलग घटना नहीं है। इससे पहले झाबुआ, भोपाल और देश के अन्य हिस्सों में सामने आई ऐसी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि आभासी दुनिया किस तरह वास्तविक जीवन पर हावी होती जा रही है और हम अनजाने में एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां संवेदनाएं, संवाद और जीवन–मूल्य स्क्रीन के पीछे दम तोड़ते जा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग अपने आप में अपराध नहीं है, न ही तकनीक शत्रु है, लेकिन जब यह बच्चों और किशोरों के लिए लत बन जाए, तो यह एक धीमा जहर बन जाती है। यह जहर चुपचाप बच्चों के मस्तिष्क में प्रवेश करता है, उनकी सोच, उनकी भावनात्मक संरचना और उनके निर्णय लेने की क्षमता को विकृत करता है। गेमिंग की दुनिया बच्चों को तात्कालिक रोमांच, आभासी जीत और काल्पनिक पहचान देती है, लेकिन धीरे–धीरे वही दुनिया उन्हें वास्तविक जीवन से काट देती है। परिवार, मित्र, पढ़ाई, प्रकृति, खेल और संवाद–सब कुछ पीछे छूटने लगता है। गाजियाबाद की तीनों बहनों का यह कदम इसी कटाव का चरम और भयावह परिणाम है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अत्यधिक ऑनलाइन गेमिंग बच्चों के मस्तिष्क में आवेग नियंत्रण को कमजोर करती है। जोखिम का आकलन करने की क्षमता घटती है और भावनात्मक अस्थिरता बढ़ती है। हार, असफलता या गेम से वंचित किए जाने की स्थिति में अवसाद, क्रोध और निराशा गहराने लगती है। कई बार बच्चे आत्महत्या जैसे चरम कदम को भी एक 'गेम ओवर' की तरह देखने लगते हैं। यह सोच अपने आप में अत्यंत खतरनाक है। आत्महत्या की प्रवृत्ति का बढ़ना केवल मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक चुनौती है, जो हमारी परवरिश, हमारी प्राथमिकताओं और हमारी नीतियों पर सवाल उठाती है। आज के परिवारों में माता–पिता की व्यस्तता, एकल परिवारों की बढ़ती संख्या और संवाद की कमी ने बच्चों को अकेलेपन की ओर धकेला है। स्मार्टफोन कई घरों में बच्चों की चुप्पी खरीदने का सबसे आसान साधन बन गया है। रोता बच्चा हो, जिद करता बच्चा हो या समय न देने की मजबूरी–मोबाइल फोन एक त्वरित समाधान बन चुका है। लेकिन यही समाधान आगे चलकर सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि बच्चा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मार्गदर्शन, स्नेह और समय चाहता है। जब यह सब उसे स्क्रीन से मिलने लगता है, तो परिवार की भूमिका स्वतः कमजोर हो जाती है। यह भी एक कठोर सत्य है कि कई माता–पिता स्वयं डिजिटल लत के शिकार हैं। ऐसे में बच्चों को रोकने का नैतिक और व्यवहारिक अधिकार भी कमजोर पड़ जाता है। हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वे मोबाइल कम चलाएं, जबकि हमारे अपने हाथों में हर समय फोन रहता है। यह दोहरा व्यवहार बच्चों के मन में भ्रम और विद्रोह दोनों पैदा करता है। इसलिए समस्या का समाधान केवल बच्चों पर नियंत्रण नहीं, बल्कि पूरे पारिवारिक वातावरण में संतुलन लाने से जुड़ा है। सरकार और समाज की भूमिका भी इस संकट में कम महत्वपूर्ण नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके सामाजिक प्रभावों पर पर्याप्त नियंत्रण और निगरानी का अभाव है। कई गेम्स में हिंसा, आक्रामकता और जोखिम भरे व्यवहार को सामान्य और रोमांचक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बच्चों के लिए आयु–उपयुक्त सामग्री, समय–सीमा और चेतावनी संकेतों को सख्ती से लागू करना अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन चुका है। सरकार को चाहिए कि वह ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल कंटेंट के लिए स्पष्ट और कठोर नियामक ढाँचा विकसित करे, जिसमें बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि हो। विद्यालयों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रह सकती। डिजिटल साक्षरता, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन–कौशल को शिक्षा का

अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए। बच्चों को यह सिखाना आवश्यक है कि तकनीक का उपयोग कैसे किया जाए, न कि तकनीक के गुलाम कैसे बना जाए। शिक्षकों को भी बच्चों के व्यवहार में होने वाले बदलावों, अकेलेपन, चिड़चिड़ेपन और अचानक गिरते शैक्षणिक प्रदर्शन जैसे संकेतों को गंभीरता से लेना होगा। मनोवैज्ञानिक सहायता को लेकर समाज में जो झिझक और संकोच है, उसे भी तोड़ना होगा। मानसिक स्वास्थ्य को कमजोरी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। यदि किसी बच्चे में अवसाद, अत्यधिक चुप्पी, आक्रामकता या आत्मघाती विचारों के संकेत दिखें, तो समय रहते विशेषज्ञ की मदद लेना अत्यंत आवश्यक है। देर करना कई बार अपूरणीय क्षति में बदल जाता है। निस्संदेह, ये आत्मघात की घटनाएं, ऑनलाइन गतिविधियों के अतिरेक से मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभाव को लेकर गंभीर सवालों को जन्म देती हैं। निश्चित रूप से आत्मघात की ये घटनाएं हमारे नीति–नियंताओं और अभिभावकों को आसन्न संकट के प्रति सचेत करती हैं। दरअसल,ये दुखद घटनाएं एक घातक प्रवृत्ति को ही उजागर करती हैं कि गेमिंग और डिजिटल संपर्क लाखों युवाओं को आभासी समुदाय और मनोरंजन तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भावनात्मक कमजोरियों,सामाजिक अलगाव और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की पूर्ति न होने जैसी समस्याओं को भी जन्म दे सकते हैं। हालांकि, वहीं दूसरी ओर समाज विज्ञानी इस बात पर भी बल देते हैं कि केवल गेमिंग या ऑनलाइन मित्रता ही आत्महत्या का कारण नहीं बन सकती हैं। निस्संदेह, आत्महत्या एक जटिल और बहुआयामी घटना है। लेकिन समस्याग्रस्त डिजिटल जुड़ाव, विशेष रूप से जब यह ऑफलाइन जीवन से अलगाव, बाधित शिक्षा और तीव्र भावनात्मक तनाव के साथ होता है तो संवेदनशील युवा मन में परेशानी को और बढ़ा सकता है। गाजियाबाद की यह घटना हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि हमने बच्चों के लिए कैसी दुनिया बनाई है। क्या हमने उन्हें संवाद दिया, या केवल उपकरण थमा दिए? क्या हमने उन्हें संस्कार दिए, या केवल सुविधाएं? क्या हमने उन्हें सुनने का समय दिया, या केवल आदेश? यह आत्ममंथन केवल पीड़ित परिवारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूरे समाज को अपने भीतर झांककर देखना होगा। यह घटना एक चेतावनी है, एक टर्निंग पॉइंट है। यदि अब भी हमने इसे एक सामान्य समाचार की तरह भुला दिया, तो भविष्य में ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी। समाज को, सरकार को और प्रत्येक परिवार को मिलकर कड़े और संवेदनशील कदम उठाने होंगे। तकनीक को नकारना समाधान नहीं है, लेकिन उसे बिना नियंत्रण स्वीकार करना भी आत्मघाती है। संतुलन, संवाद और सहभागिता ही बच्चों की सुरक्षा का वास्तविक आधार हैं। गाजियाबाद की तीनों बहनों हो या कूल्लु के किशोर की असमय मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि अगर हमने अभी नहीं संभला, तो यह इलेक्ट्रॉनिक खतरा हमारे घरों, हमारे भविष्य और हमारी संवेदनाओं को निगलता चला जाएगा। यह समय है जागने का, सोचने का और ठोस कदम उठाने का–क्योंकि यह सवाल केवल तकनीक का नहीं, बल्कि जीवन का है।

बुंदेलखंड में 'हर घर नल' से बहती उम्मीद की धारा

गांव की महिलाओं को अब पानी के लिए नहीं तलाश करने पड़ते कुंए हैंडपंपों में लगने वाली भीड़ से मिला छुटकारा, सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ी सिर्फ आधार कार्ड दिया और कनैक्शन हो गया, सार्वजनिक नल भी लगे

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। बुंदेलखंड के लोगों के लिए यह किसी सपने से कम नहीं कि आज उन्हें उनके घर में ही पानी मिल रहा है। इस क्षेत्र में पानी की किल्लत से भुखमरी और गरीबी की जाने कितनी कहानियां हैं। सिर पर घड़ा रखकर दूरदराज से पानी लाती एक महिला की तस्वीर ही यहां के जिलों की पहचान बन गई थी। सालों साल तक यहां की महिलाओं ने पानी का संकट भुगता है। दूरदराज के कुंओं तक जाकर पानी खींचने के साथ ही हैंडपंप पर पानी के लिए लाइनें लगाई हैं। लेकिन अब यह सब अतीत की बातें हैं। अब सड़कों पर दूर से ही दिखनेवाली पानी की टंकियां उम्मीदों की जलधारा हैं। बात महोबा की करें तो यहां के लोगों ने पानी की किल्लत से लंबे समय तक दुर्दिन भरे दिन देखे हैं। कभी यहां वाटर ट्रेन से पानी पहुंचाने की नौबत आ गई थी। लोग घड़ा भर पानी के लिए जाने कहां–कहां तक भटकते थे। अब यहां दूर से ही दिखाई देने वाले वाटर टैंक नई कहानी कहते हैं। इस जिले में जल जीवन मिशन के तहत पांच परियोजनाओं के सहारे एक लाख 12 हजार से अधिक घरों को पाइपलाइन की कनेक्टिविटी दी जा चुकी है। हालांकि इसके लिए 1131 किलोमीटर सड़कों को क्षतिग्रस्त किया गया। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के दौरान लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना अवश्य करना पड़ा। महोबा के अरशद कहते हैं कि कोई योजना शुरू होने पर थोड़ी–बहुत परेशानी तो होती ही है। लेकिन, अब हर घर नल यहां के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। चित्रकूट में सिलौटा ग्राम मुस्तकिल समूह योजना की बात करें तो इससे जुड़े विकास खंड पहाड़ी, रामनगर और मानिकपुर में सवा लाख लोगों के लिए पानी की समस्या खत्म हो गई है। मानिकपुर के उन लोगों का दर्द महसूस कीजिए जो कभी लगभग एक किमी दूर से पानी लाया करते थे।...और इस समस्या की वजह से वहां लोग अपनी बेटियां ब्याहने को आसानी से तैयार नहीं होते थे। उनके लिए यह पानी जिंदगी है, बच्चों का भविष्य है। योजना के तहत पूरे क्षेत्र में 576 किमी की पाइप लाइन बिछाई जानी है, जिसमें 572 किमी बिछा दी गई है। 17 ओवरहेड टैंक हैं जहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से रोज पानी लाया जा रहा। यमुना नदी से पानी लाकर इस प्लांट में संशोधित करके टैंकों में चढ़ाकर लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा। बरहट की ग्राम प्रधान श्रीमती रज्जन देवी इस योजना का चर्चा करते हुए भावुक हो जाती हैं। कहती हैं कि हम योगी–मोदी सरकार के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों को बीमारियों से बचाने का इंतजाम कर दिया। हमारे बच्चे अब नहो–धोकर स्कूल जाते हैं। उनमें स्वच्छता का भाव स्वतः ही आने लगा है। चित्रकूट में सिलौटा के साथ ही रैपुरा, चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजनाएं चल रही हैं और यह सारी योजनाएं उम्मीद की वह धारा हैं जिसके बारे में लोगों ने सोचा तक नहीं था। रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के तहत 19570 परिवारों को नल से पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इन सभी घरों में नल लग गए हैं और 60 राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति शुरू कर दी गई है। योजना के तहत आच्छादित मदना गांव के निवासी चुनबाद यादव बताते हैं कि हमारी बड़ी समस्या दूर हुई है। अपने लिए पानी का इंतजाम मुश्किल था, जानवरों की तो बात ही दूर। अब हमें परेशान नहीं होना पड़ रहा। लोगों के लिए यह सिर्फ एक नल की बात हो सकती है लेकिन बुंदेलखंड के लिए यह वरदान है। यह वस्तुतः उस संकल्प की सिद्धि है, जिसे मोदी–योगी सरकार ने साधना के रूप में लिया। झांसी के बडा गांव, चिरगांव और बंगरा में अंतिम छोर के गांव तक जल जीवन मिशन की पाइप लाइन बिछ गई है। झासी जिले के बंगरा विकासखंड में स्थित गैरहा ग्राम पंचायत के 65 साल के कामता प्रसाद भावुक हो गए। बोले कि यह दिन देखने के लिए आंखें तरस गईं थीं। जिला मुख्यालय से दूर बसे इस गांव की विवाहिता शगुन बताती हैं कि उन्हें पहले गांव से आधा किमी दूर पानी लेना जाना पड़ता था और बारिश के समय बड़ी मुश्किल होती थी। झांसी जिले के बंगरा ब्लाक की ग्राम पंचायत पचवारा में बहू बन कर जब रागिनी आईं तो उन्हें सरकारी हैंड पंप से पानी ले जाना पडता था। अब वे टोंटी खोलते हुए दिखाती हैं कि

देखिये कितना साफ पानी है। गरीब परिवार की बहू खुश है कि मजदूरी करने वाले उनके पति मुकेश कुमार को एक पैसा तक नहीं देना पड़ा और नल का कनेक्शन हो गया। ग्राम पंचायत प्रधान अखिलेश रावत बताते हैं कि उनके गांव में एक हजार कनेक्शन हुए हैं। दलित बाहुल्य गांव में योगी सरकार में बनाए गए आरोग्य मंदिर में भी जल जीवन मिशन के तहत नल लगा है, जहां मरीजों, तीमारदारों के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध है। सरकारी स्कूलों में भी बच्चे स्वच्छ पानी पी रहे हैं। जल जीवन मिशन के अधिशाषी अभियंता रणविजय सिंह बताते हैं कि इस स्कीम के तहत 42 गांव आच्छादित हैं और इन गांवों में 11 हजार 437 कनेक्शन हुए हैं। बांदा का नाम आते ही सूखा, पानी की कमी और प्यास आदि शब्द अपने आप दिमाग में कौंधने लगते थे। अब यहां अमलीकौर पेयजल परियोजना और खटान पेयजल परियोजना से 544 गावों में पानी पहुंचा है। 82266 घरों में कनेक्शन किए जा चुके हैं। बड़ोखर खुर्द ब्लाक के बांधा पुरवा गांव के रहने वाले परदेशी ने बताया कि पहले हमें पानी के लिए पहले परेशान होना पड़ता था। वहीं अब हमको हमारे घरों में ही स्वच्छ पानी मिल रहा है। जल निगम के अधिशासी अभियंता विमल कुमार वर्मा ने बताया कि पाइपलाइन डालने के लिए जिन सड़कों को खोदा गया था। उनको भी ठीक कर दिया गया है। हमीरपुर में भी दो पेयजल परियोजनाएं चल रही हैं जहां 322 में से 320 गांवों में घरों तक नल से पानी पहुंचाया जा रहा है। यहां के लोगों की जिंदगी में यह योजना बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है।

हिंदूवादी संगठन का मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद गिराने का ऐलान, राजधानी में होर्डिंग्स लगीं

संवाददाता

लखनऊ। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने 10 फरवरी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जाने का ऐलान किया है। लखनऊ में संगठन की ओर से होर्डिंग लगाई गई हैं। उस पर लिखा– हुमायूं हम आएंगे३बाबरी फिर से गिराएंगे। बंटोगे तो कटोगे। हिंदुओं की विरोधी सरकार में, इस बार होगा मुर्शिदाबाद में नई बाबरी पर आरपार। होर्डिंग पर 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद चलने की अपील भी की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का फोटो भी लगाया गया है। लखनऊ के 1090 चौराहा से गोमती नगर के बीच शनिवार देर रात में 5 होर्डिंग्स लगाई गई है। उनपे मुर्शिदाबाद में निर्माणाधीन बाबरी मस्जिद का उल्लेख किया गया है। एक ओर भगवान श्रीराम और विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय की तस्वीर लगी है। दूसरी ओर ममता बनर्जी और विधायक हुमायूं कबीर की तस्वीर है। हुमायूं को बाबर का गेटअप दिया गया है। विश्व हिंदू रक्षा

परिषद (वीएचआरपी) ने होर्डिंग लगवाने के साथ ही यह भी ऐलान किया है कि कार्यकर्ता 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि संगठन ने 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद जाने का कार्यक्रम तय किया है। होर्डिंग में इसी कार्यक्रम को लेकर संदेश दिया गया है।गोपाल राय ने कहा पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर ने 11 फरवरी से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू करने की बात की है। इस वजह से हम लोग 10 फरवरी को यहां से मुर्शिदाबाद जाने की तैयारी कर लें। 10 फरवरी को हम लोग यहां से निकलें। वहां 11 फरवरी की सुबह प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहां हुमायूं कबीर की कब्र खोदने का भी काम करेंगे। वहां की हिंदू विरोधी सरकार को भी उखाड़ फेंकनी है। होर्डिंग लगने के बाद पुलिस–प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने का दावा किया है।

बीबीडी थाने पर धरने पर बैठीं सपा पार्षद, बोलीं विधायक बेदी राम के खिलाफ हो एफआईआर

संवाददाता

लखनऊ। सपा पार्षद ममता रावत अपने समर्थकों के साथ बीबीडी थाने पर धरना शुरू कर दिया है। वह सुभासपा विधायक बेदी राम पर मुकदमा नहीं दर्ज होने को लेकर आक्रोशित हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक विधायक के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज हो जाएगा, थाने से नहीं हटेंगी। उनके समर्थकों में भी भारी आक्रोश है। वे विधायक बेदी राम मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। समर्थकों का कहना है टेंट मंगवाकर धरना देंगे। इससे थाने पर गहमागहमी की स्थिति बनी हुई है। वहीं, नगर निगम की ओर से भी आज विधायक बेदी राम के खिलाफ शिकायत दी जा सकती है। सपा पार्षद ममता रावत ने 7, फरवरी, शनिवार को विधायक बेदी राम के खिलाफ बीबीडी थाने में शिकायत दी थी। उनका आरोप है कि पुलिस ने मामले में मुकदमा नहीं दर्ज किया है। इस पर

आज, 8 फरवरी को वह अपने समर्थकों के साथ बीबीडी थाने आई हैं। पार्षद ममता रावत का कहना है कि सुभासपा विधायक बेदीराम ने मेरे लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। गालियां दी हैं। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी इस संबंध में अवगत कराया है। मेयर सुषमा खर्कवाल को भी लिखित में शिकायत दे चुकी हैं। ममता चौधरी ने इस प्रकरण को लेकर काफी आक्रोशि हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा विधायक बेदी राम ने मुझे गालियां दी हैं। मैं इसकी एफआईआर कराउंगी। कार्रवाई नहीं होने पर धरना दूंगी। विधायक का यह अधिकार नहीं है कि एक महिला पार्षद को गालियां दें। गोमतीनगर के भरवारा के गंगोत्री विहार फेज–टू में नाले पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद चल रहा है। यहां सुभाषपा विधायक बेदीराम का मैरिज हॉल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विधायक ने नाले की जमीन पर कब्जा कर रखा है।

बिश्नोई गैंग के नाम पर 30 लाख की रंगदारी मांगी, कारोबारी का पूर्व सेल्समैन गिरफ्तार

संवाददाता

लखनऊ। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में एक दवा कारोबारी को कुख्यात बिश्नोई गैंग के नाम से 30 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। दवा कारोबारी गौरव बत्रा ने सरोजनी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चिनहट के रोहित रेजिडेंसी, विकल्प खंड निवासी गौरव बत्रा सरोजनी नगर के हिन्द नगर, कानपुर रोड स्थित करुण इंटरप्राइजेज में प्रबंधक हैं। उनके अनुसार, 30 जनवरी 2026 की सुबह करीब साढ़े नौ बजे जब वे अपने कार्यालय पहुंचे, तो फर्म के गार्ड सत्य नारायण ने उन्हें एक बंद लिफाफा दिया। उस पर उनका नाम लिखा था। गार्ड ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने रात में लिफाफा उन्हें देने के लिए दिया था। गौरव बत्रा ने बताया कि लिफाफे पर हिंदी और अंग्रेजी में उनका नाम लिखा था। श्केवल वही खोलेंश लिखा था। लिफाफा खोलने पर अंदर हाथ से लिखा एक पत्र निकला। पत्र में खुद को बिश्नोई गैंग, पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़ा बताते हुए 30 लाख रुपये की मांग की गई थी। पत्र में यह भी ध मकी दी गई थी कि यदि रकम नहीं दी गई, तो गौरव बत्रा, उनके गोदाम और कार्यालय के कर्मचारियों को जान से मार दिया जाएगा। इस ध मकी भरे पत्र के बाद से वह काफी डरे हुए हैं। उन्हें अपनी तथा कर्मचारियों की जान का खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने सरोजनी नगर थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस की जांच में आया है कि दवा कारोबारी के पूर्व कर्मचारी ने ही यह हरकत की है। इस पर पुलिस ने कारोबारी के पूर्व सेल्समैन उमेश कुमार यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी उमेश से पूछताछ की गई। उसने बताया कि वह गौरव

बत्रा के गोदाम पर काम करता था। उसे सेटलमेंट ड्यूज नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उसने अगस्त 2025 में काम छोड़ दिया था। उसने 7 लाख रुपए बैंक से लोन ले रखा है, जिसकी किस्तें न अदा कर पाने की वजह से परेशान था। उसे पता था कि गौरव बत्रा अच्छा पैसा कमाते हैं। उसने फिल्में व वेब सीरीज काफी देखी है। जिसे देखकर उससे रंगदारी वसूलने का आइडिया आया। तब उसने यह प्लान बनाया और अपनी स्कूटी से हिंद नगर पहुंचा। स्कूटी को छुपा कर खड़ी दी। शॉल ओढ़कर हेलमेट लगाकर दवा गोदाम पहुंचा। वहां गार्ड को लिफाफा देकर चुपके से निकल गया। लिफाफे के ऊपर लिख रखा था कि सिर्फ दवा कारोबारी गौरव बत्रा ही इसे खोलें। उसने अंदर यह भी लिखा था कि 15 दिन के अंदर 30 लाख रुपए दे दें, नहीं तो उन्हें और उनके कर्मचारियों को जान से मार दिया जाएगा। अंदर यह भी लिखा कि अगर यह रकम देना चाहते हैं तो गेट के दोनों ओर भगवा झंडा लगा दें, जिससे हम समझ जाएंगे कि पैसे मिले जाएंगे। पुलिस की जांच में आया कि आरोपी उमेश कुमार ने यह पत्र खुद अपने हाथ से लिखा था। पुलिस का कहना है कि घटना स्थल और आसपास लगे करीब 100 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। उसकी मदद से आरोपी तक पहुंचे। आरोपी को बिजनौर के रहीमाबाद रोड से आज दोपहर करीब 12 बजे गिरफ्तार किया गया। उसके पास से घटना में इस्तेमाल की गई स्कूटी, हेलमेट और शॉल बरामद की गई। उमेश कुमार यादव मूल रूप से बलिया जिले के खजुरी थाना क्षेत्र के बिसहर गांव का रहने वाला है। वर्तमान में बिजनौर थाना क्षेत्र के सीआरपीएफ कैंपस के पास सैनिक एन्क्लेव में रहता था।

मतदाता सूची में पात्र युवाओं व महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सीईओ ने की समीक्षा बैठक

युवाओं एवं महिलाओं को मतदान के अधिकार के प्रति किया जाए जागरूक संबंधित विभाग पात्र युवा व महिला मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने में करें सहयोग

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण–2026 के अन्तर्गत शनिवार को पात्र मतदाताओं में 18 से 20 आयु वर्ग के युवा तथा महिलाओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के उद्देश्य से समस्त जनपदों के उपजिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों जैसे विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला कल्याण, माध्यमिक व उच्चशिक्षा विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को पात्र युवा, किशोरियों व नवविवाहिता महिला मतदाताओं के नाम सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बड़ी संख्या में 18 से 20 वर्ष की आयु वर्ग के युवा मतदाता अभी भी मतदाता सूची में शामिल नहीं है। उन्होंने ऐसे सभी पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराए जाने हेतु अभियान के तौर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपदों में समस्त शैक्षणिक संस्थानों यथा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज तथा अन्य समस्त शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को मतदाता साक्षरता क्लब के माध्यम से मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक किया जाये। उन्हें अपने मतदान के अधिकारों से अवगत कराया जाय जिससे की सभी युवा अपनी मनपसंद की सरकार चुनने के लिए और लोकतंत्र में हिस्सेदार बनने के लिए मतदाता सूची में बढ़–चढ़कर अपना नाम सम्मिलित कर सकें। साथ ही उन्होंने सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष अभियान चलाकर पात्र छात्र–छात्राओं का ऑनलाइन पोर्टल www.voters.eci.gov.in तथा ECINET मोबाइल ऐप अथवा बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से ऑफलाइन घोषणा पत्र सहित फॉर्म–6 भरवाकर मतदाता सूची में शामिल कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि जिन छात्र–छात्राओं की आयु दिनांक 01.01.2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उनका शत–प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाय। जिन छात्र–छात्राओं की आयु दिनांक 01.10.2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही हो उनका भी फार्म–6 एडवांस फार्म के रूप में भरवाया जा सकता है। फार्म 6 के साथ घोषणा पत्र भरने हेतु वर्ष 2003 की अंतिम मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाईटों पर उपलब्ध है जहाँ से उसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इस मतदाता सूची की प्रतिलिपि सभी बूथ लेविल अधिकारियों के पास भी उपलब्ध है। उन्होंने अधिकारियों को इन तथ्यों का भी व्यापक प्रचार–प्रसार कराए जाने के निर्देश दिये। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 27 अक्टूबर 2025 तक की मतदाता सूची में महिलाओं का अनुपात प्रति हज़ार पुरुषों की तुलना में 877 था जो कि 6 जनवरी 2026 को जारी आलेख्य मतदाता सूची में घटकर 824 रह गया है। इससे स्पष्ट होता है की बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं के नाम गणना प्रपत्र ना भरे जाने के कारण छूट गए हैं। कई महिलाएं विवाह के पश्चात अपने मायके के स्थान पर पंजीकृत होने के कारण ससुराल में गणना प्रपत्र नहीं भर सकी। इनको लक्षित करते हुए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों यथा राष्ट्रीय आजीविका मिशन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कार्यरत महिला समूह की दीदी, चिकित्सा विभाग के अंतर्गत कार्य कर रही आशा तथा एएनएम बहनें, बाल विकास पुष्टाहार विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकत्री तथा सुपरवाइजर, के सहयोग से नव विवाहित महिलाओं और किशोरियों के नाम आलेख्य मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है उन सभी पात्र महिलाओं का नाम घोषणा पत्र सहित फॉर्म 6 भरवा कर मतदाता सूची में शामिल करने का प्रयास करें। जन प्रतिनिधियों को चुनने में महिलाओं की भूमिका एवं सहभागिता बढ़ाना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि अगले 15 दिनों तक मतदाता सूची में पात्र मतदाताओं का नाम दर्ज कराने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाए, जिसका प्रचार–प्रसार प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया में किया जाये फार्म–6 भरवाने हेतु संबंधित कार्मिकों को समुचित प्रशिक्षण भी दिया जाना सुनिश्चित किया जाय जिससे मतदाता सूची में समस्त पात्र नागरिकों का नाम शामिल हो सके।

पाकिस्तान पीएम का पुतला फूंका गया,पाकिस्तान को आतंकी मुल्क घोषित करने की मांग

संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ के बड़ाइमाम बाड़ा पर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हैदरी टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शिया समुदाय की मस्जिद पर हुए हमले का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने नाराजगी जताते हुए पाकिस्तान का झंडा इमामबाड़ा के गेट पर लगाया जिसपर लोग जूता चप्पल पहनकर गुजरे। हमले का विरोध करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और सेना अध्यक्ष आसिफ मुनीर का पुतला फूंका। पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए आतंकी देश घोषित करने की मांग किया।

शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी ने कहा कि विगत 3 महीनों में पाकिस्तान में शिया समुदाय पर ये दूसरा बड़ा हमला है। इसमें बड़ी संख्या में बेगुनाहों की मौत हुई हुआ। हम लोग लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं मगर पाकिस्तान सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है।

ब्राह्मणों पर फोकस, मिशन–2027 की तैयारी, क्या मायावती फिर खेलेंगी 2007 वाला ब्राह्मण कार्ड?

संवाददाता

लखनऊ। यूपी में अगड़ा बनाम पिछड़ा को लेकर चल रही सियासी घमासान के बीच बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर अपनी पुरानी लेकिन आजमाई हुई रणनीति की ओर लौटती दिख रही है...बीएसपी सुप्रीमो मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सवर्ण मतदाताओं, खासकर ब्राह्मण वोट बैंक को साथ लाने की ठोस तैयारी में जुट गई हैं. ..पार्टी का मानना है कि यदि अपने पारंपरिक बेस वोटर के साथ सवर्ण समाज का समर्थन मिल जाए, तो सत्ता की राह एक बार फिर आसान हो सकती है। हाल के दिनों में मायावती के बयानों पर नजर डालें तो साफ संकेत मिलता है कि ब्राह्मण समाज उनके राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में है... लगातार सार्वजनिक मंचों से वे ब्राह्मणों के सम्मान, सुरक्षा और हितों की बात कर रही हैं... बीते शनिवार हुई अहम बैठक में भी मायावती ने ब्राह्मण समाज के योगदान और उनके अधिकारों का जिक्र करते हुए पार्टी नेताओं को इस दिशा में सक्रिय रहने के निर्देश दिए।

बीएसपी नेतृत्व को ये भी याद है कि अतीत में सवर्णों के सहयोग से ही पार्टी ने सत्ता का स्वाद चखा था... साल 2007 के विधानसभा चुनाव में 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के नारे के साथ मायावती ने दलित, पिछड़े और सवर्ण समाज को एक मंच पर लाकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी३ अब करीब दो दशक बाद एक बार फिर उसी सामाजिक समीकरण को दोहराने की कोशिश हो रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती अपने कोर वोट बैंक के साथ–साथ सवर्ण समाज को जोड़कर एक व्यापक सामाजिक गठबंधन खड़ा करना चाहती हैं...और यही वजह है

कि ब्राह्मणों को लेकर उनका रुख लगातार नरम नजर आ रहा है... पार्टी के भीतर भी इस रणनीति को लेकर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दिनों में बीएसपी के बड़े नेता जिलों का दौरा शुरू करेंगे... इन दौरों में खासतौर पर ब्राह्मण समाज के प्रभावशाली लोगों से संवाद, बैठकें और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे... पार्टी का उद्देश्य जमीनी स्तर पर भरोसा कायम करना और ये संदेश देना है कि बीएसपी सिर्फ एक वर्ग की नहीं, बल्कि सर्व समाज की पार्टी है...और वही पुराना नारा है 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय'। कुल मिलाकर, 2027 विधानसभा चुनाव के लिए मायावती ने ब्राह्मणों को केंद्र में रखकर बिगुल फूंक दिया है.... सवाल बस इतना है कि क्या 2007 का सर्वजन प्रयोग एक बार फिर बीएसपी को सत्ता के शिखर तक पहुंचा पाएगा... या बदलते राजनीतिक हालात में ये रणनीति नई चुनौतियों से जूझती नजर आएंगी...इसका जवाब आने वाले महीनों की राजनीति में साफ होता नजर आएगा।

संक्षिप्त

ईट लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली में घुसी वैगनआर कार, महिला समेत 2 लोग घायल

संवाददाता

लखनऊ। निगोहां थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव के पास रविवार दोपहर भीषण हादसा हो गया। एक वैगनआर कार ईंट से लदी ट्रैक्टर–ट्रॉली में पीछे से घुस गई। हादसे में कार सवार महिला पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए।उनकी पहचान सरोजनीनगर के विकास और संगीता गंभीर रूप से घायल हो गईं। टक्कर इतनी भीषण रही कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रॉली पलट गई। इस दौरान पूर्व जल शक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह निगोहां क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। हादसा देखकर उन्होंने अपना काफिला रोका। अपनी सुरक्षा में लगे एस्कॉर्ट वाहन से घायलों को मोहनलालगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। सीएचसी में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद संगीता और विकास की हालत गंभीर देखते हुए दोनों को ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया।

इस दौरान पूर्व मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह अस्पताल में मौजूद रहे। घायलों के रेफर होने तक व्यवस्था संभाली। पूर्व मंत्री ने एम्बुलेंस से घायलों को ट्रॉमा सेंटर भेजवाने की व्यवस्था कराई। पीजीआई ट्रॉमा सेंटर प्रशासन से बात कर दोनों घायलों का तत्काल और बेहतर इलाज सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

शेफ हरपाल सिंह सोखी ने देहरादून में लाइव क्यूलिनरी मास्टरक्लास की मेज़बानी की

बीएनई

देहरादून। देहरादून में हाल ही में एक यादगार क्यूलिनरी शाम देखने को मिली, जब प्रसिद्ध शेफ और टेलीविज़न पर्सनैलिटी शेफ हरपाल सिंह सोखी ने करिगरी में एक लाइव क्यूलिनरी मास्टरक्लास का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में फूड लवर्स, मीडिया प्रतिनिधि और विशेष अतिथि शामिल हुए, जिन्होंने भारतीय स्वाद, यादों और स्ट्रीट फूड संस्कृति से जुड़ा एक गहरा अनुभव साझा किया। यह मास्टरक्लास एक लाइव और इंटरैक्टिव सत्र के रूप में डिज़ाइन की गई थी, जिसमें शेफ हरपाल ने चुने हुए प्रतिभागियों के साथ मिलकर खाना बनाया। इस दौरान उन्होंने हर डिश के पीछे की कहानियाँ साझा की और पारंपरिक स्वादों को आधुनिक प्रस्तुति के साथ संतुलित करने की तकनीकें भी बताईं। यह मेनू भारत भर में उनकी निजी भोजन यात्रा को दर्शाता है बनारस के दीनानाथ महाराज से प्रेरित दीनानाथ की टमाटर चाट, जो वाराणसी के घाटों के कालातीत स्वादों को समेटे हुए है, से लेकर क्लचे–छोले पकौड़े पॉकेट्स, जो उनके बचपन की उन यादों से निकले हैं जब वे अपने पिता के साथ लुधियाना की गलियों में स्ट्रीट फूड का आनंद लिया करते थे। यह यात्रा आगे बढ़ती है जलेबी वाफ़ल्स के साथ भारत की सड़कों के कारीगरों को सम्मान देते हुए, पारंपरिक मिठाई को नई पीढ़ी के लिए एक आधुनिक, गॉरमेट अंदाज़ में पेश किया गया है। मेहमानों के लिए एक विशेष रूप से तैयार किया गया बुफे भी रखा गया, जिसमें करिगरों की दाल मखनी, कढ़ाही पनीर पालक मेथी, सब्ज़ बिरयानी, इंडियन ब्रेड्स और मिर्चा वाला हलवा जैसी पारंपरिक मिठाइयाँ शामिल थीं। पेय पदार्थों में क्षेत्रीय भारतीय ड्रिंक्स को प्रमुखता दी गई, खासतौर पर बेला चमेली शरबत, जो बीकानेर के छोटे कारीगरों और पारंपरिक दुकानों की विरासत को सम्मान देता है। मास्टरक्लास के बारे में बात करते हुए शेफ हरपाल सिंह सोखी ने कहा, मेरे लिए खाना सिर्फ रेसिपीज़ तक सीमित नहीं है, यह लोगों, जगहों और यादों से जुड़ा होता है। देहरादून में हुई यह मास्टरक्लास उन्हीं कहानियों को थाली तक लाने की कोशिश थी बनारस से पंजाब तक की यात्रा, देर्शकों के साथ मिलकर खाना बनाना, भारत के कारीगरों और उनकी कारीगरी को अपनी रसोइयों में सम्मान देना, और हमारी क्षेत्रीय व्यंजनों का उत्सव मनाना। जब लोग साथ मिलकर

खाना बनाते हैं, तब भोजन एक उत्सव बन जाता है। यह शाम पारंपरिक स्वागत के साथ शुरू हुई, जिसके बाद ढोल के साथ शेफ हरपाल की भव्य एंट्री हुई। कार्यक्रम में दर्शकों की भागीदारी के साथ लाइव कैकिंग सेशंस और एक विस्तृत मीट–एंड–ग्रीट सेशन भी शामिल था। मेहमानों ने भोजन को उसी रूप में अनुभव किया, जैसा उसका असली आनंद होता है ताज़ा बना हुआ और साथ बैठकर साझा किया गया। देहरादून मास्टरक्लास ने एक बार फिर शेफ हरपाल सिंह सोखी के उस विश्वास को मज़बूत किया, जिसमें वे भारतीय पाक विरासत को संरक्षित करते हुए उसे नए दौर और नई पीढ़ी से जोड़ने पर जोर देते हैं। कार्यक्रम का समापन स्वाद, सीख और गर्मजोशी से भरी यादों के साथ हुआ।

नवोत्थान और विकसित भारत-2047 के विजन का सशक्त दस्तावेज है केन्द्रीय बजट : मनोहर लाल

केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबध्द

बीएनई

रायपुर। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने केन्द्रीय बजट को नवोत्थान और समावेशी विकास का वाहक बताते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत–2047 के दीर्घकालिक विजन को साकार करने वाला एक सशक्त दस्तावेज है। वे राजधानी रायपुर में एक दिवसीय प्रवास के दौरान आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। केन्द्रीय मंत्री लाल ने कहा कि इस बजट में अगले 25 वर्षों के लिए देश के आर्थिक, सामाजिक एवं बुनियादी ढांचे के विकास की स्पष्ट दिशा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि यह बजट पहली बार कर्तव्य भवन में तैयार किया गया है, जो शासन व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। बजट में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को भी सम्मिलित किया गया है, जिससे आगामी वर्षों में राज्यों के विकास को नई गति मिलेगी। मनोहर लाल ने विश्वास जताया कि बजट प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन से बिजली, आवास, शहरी विकास एवं अधोसंरचना क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। प्रेस वार्ता में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू, प्रदेश के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, सांसद संतोष पाण्डेय एवं बृजमोहन अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

भारत ने दोहराया पुराना रूख, कहा- विविधता जारी रहेगी, ट्रंप बोले- खरीदने पर फिर लगेगा टैरिफ

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। अमेरिका की ओर से भारतीय उत्पादों पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क को वापस लेने के बाद भी भारत ने यह साफ नहीं किया है कि वह रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करेगा या नहीं। शनिवार को भारत सरकार ने इस मुद्दे पर न तो पुष्टि की और न ही खंडन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क को हटाने का फैसला किया। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब कुछ दिन पहले ट्रंप ने भारत–अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा की थी। रूसी तेल खरीदा, तो फिर लगेगा 25 फीसदी टैरिफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत के रूसी तेल की खरीद रोकने और व्यापार बाधाएं कम करने के बदले भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया जाएगा। अपने आदेश में ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी तेल आयात रोकने, अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदने और अगले 10 वर्षों के लिए रक्षा सहयोग बढ़ाने के ढांचे पर सहमति जताई है। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर अमेरिका के वाणिज्य सचिव को यह पता चलता है कि भारत ने फिर से रूसी तेल आयात शुरू किया है, तो भारत

पर दोबारा 25 प्रतिशत शुल्क और अन्य कदमों पर विचार किया जा सकता है। ट्रंप के दावे पर क्या बोला विदेश मंत्रालय? हालांकि, भारतीय अधिकारियों ने ट्रंप के इस दावे पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया। पूछे जाने पर उन्होंने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के हालिया बयान का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि बाजार स्थितियों और अंतरराष्ट्रीय हालात के अनुसार ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना भारत की रणनीति का हिस्सा है। भारत ने पहले भी स्पष्ट किया है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हितों और बाजार की परिस्थितियों पर आधारित है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद भारत ने रियायती दरों पर रूसी तेल की खरीद बढ़ाई थी, हालांकि हाल के हफ्तों में इसमें गिरावट दर्ज की गई है।

US ट्रेड डील के विरोध में किसान-मजदूर संगठनों का संयुक्त मोर्चा

सभी संगठनों ने किसान–मजदूरों, युवाओं और आम जनता से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की
आगामी माह में दिल्ली में विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी

बीएनई

नई दिल्ली। US ट्रेड डील के विरोध में किसान–मजदूर संगठनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी संगठनों ने एक स्वर में इस डील को किसान–मजदूर और देश विरोधी करार दिया।बैठक में वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प के दबाव में देश की संप्रभुता के साथ समझौता किया है। इस ट्रेड डील से देश की खेती–किसानी तबाह हो जाएगी और भारत, अमेरिका के कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों का डंपिंग ग्राउंड बनकर रह जाएगा। संगठनों ने आशंका जताई कि इस समझौते सेकृकिसानों की आय और स्वायत्तता पर गंभीर संकट आएगा.स्थानीय उत्पादन खत्म होगा.मजदूरों के रोजगार और अधिकारों पर सीधा हमला होगा.देश की संप्रभुता, खेती–किसानी और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

मुख्य मांगें

US ट्रेड डील को तत्काल रद्द किया जाए
मजदूर विरोधी टट बग्राम योजना को रद्द किया जाए
मनरेगा की पूर्ण बहाली सुनिश्चित की जाए
इन मांगों को लेकर आंदोलन को आगे बढ़ाने हेतु एक समन्वय समिति का गठन किया गया है, जो देशभर के विभिन्न किसान–मजदूर संगठनों से संवाद करेगी।
समन्वय समिति के सदस्य
उत्तर प्रदेश / पंजाब
चौ. हरपाल सिंह बिलारी – अध्यक्ष, भाकियू (असली)
प्रबल प्रताप शाही
विपिन खारी – भाकियू बलराज
अतर सिंह – राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच
फरीद अहमद खान – मनरेगा बचाओ मोर्चा
राजपाल यादव – भाकियू (असली) हरियाणा / राजस्थान / हिमाचल
सुमन हुड्डा – भाकियू (चढ़ूनी)
धीरज गाबा – राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच
मध्य प्रदेश / महाराष्ट्र
राहुल निहोरे – श्रमिक संघर्ष मोर्चा, इंदौर
दिल्ली
निशांत
विवेक श्रीवास्तव
आगामी कार्यक्रम
15 फ़रवरी 2026 – इंदौर (मध्य प्रदेश) : बड़ी पंचायत
18 फ़रवरी 2026 – मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) : किसान–मजदूर महापंचायत
23 मार्च 2026 – पीपली (हरियाणा) रू राज्य स्तरीय पंचायत
आगामी माह में दिल्ली में विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी
सभी संगठनों ने किसान–मजदूरों, युवाओं और आम जनता से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है।

संक्षिप्त

सूर्यकुमार ने इस मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ा, हसरंगा की बराबरी पर पहुंचे अर्शदीप

एजेंसी

मुंबई। भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अमेरिका के खिलाफ टी20 विश्व कप के मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया। सूर्यकुमार की दमदार पारी की मदद से ही भारत अमेरिका के सामने चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में सफल रहा और उनकी पारी ने मैच में अंतर पैदा किया जिससे भारतीय टीम जीत दर्ज कर सकी। सूर्यकुमार को उनकी इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। भारत की जीत से शुरुआत भारत ने टी20 विश्व कप 2026 के अपने पहले मुकाबले में अमेरिका को 29 रन से हराकर शानदार आगाज किया है। शनिवार को वानखेड़े में खेले गए ग्रुप मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने सूर्यकुमार यादव की नाबाद 84 रनों की पारी के दम पर 20 ओवर में नौ विकेट पर 161 रन बनाए। जवाब में अमेरिका निर्धारित ओवरों में आठ विकेट खोकर 132 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। सूर्यकुमार ने हासिल की उपलब्धि सूर्यकुमार ने अमेरिका के खिलाफ अपनी शानदार पारी से कई उपलब्धियां अपने नाम दर्ज की। सूर्यकुमार इसके साथ ही भारत के लिए टी20 में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ मैच का पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

7500 गोशालाएं बनेंगी कैटल फूड सिक्योरिटी हब

हर गोशाला से जुड़ेंगे 50–100 किसान, संरक्षण केंद्र के साथ गोशालाओं को हरा चारा उत्पादन का बेहतर स्रोत बनाएगी योगी सरकार
गोशालाओं में बड़े पैमाने पर लगाए जाएंगे सहजन के पौधे व नेपियर घास, किसानों की आमदनी व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश की गोशालाओं को अब केवल गोवंश संरक्षण तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें कैटल फूड सिक्योरिटी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। योगी सरकार की इस दूरदर्शी पहल के तहत प्रदेश की 7500 गोशालाओं और उनके आसपास के क्षेत्र को हरा चारा उत्पादन का सशक्त केंद्र बनाया जाएगा, जिससे गोवंश संरक्षण के साथ–साथ किसानों की आमदनी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

संरक्षण से उत्पादन की ओर गोशालाएं

उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि "मिशन फॉडर" के नाम से शुरू हो रहे इस प्रदेशव्यापी अभियान का उद्देश्य गोशालाओं को आत्मनिर्भर इकाइयों के रूप में विकसित करना है। इसके तहत हर गोशाला को 50 से 100 किसानों के नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, ताकि चारा उत्पादन, विपणन और उचित मूल्य की व्यवस्थित श्रृंखला तैयार हो सके। इससे किसान भी आत्मनिर्भर बनेंगे और गोशालाओं को सतत रूप से पौष्टिक हरा चारा उपलब्ध होगा।

मोरिंगा–नेपियर से बदलेगी तस्वीर

मिशन फॉडर के अंतर्गत गोशालाओं की उपलब्ध भूमि का अधिकतम उपयोग करते हुए मोरिंगा (सहजन) और नेपियर घास का बड़े पैमाने पर रोपण कराया जाएगा। इसमें गन्ना घास, सुबबूल, ढैंचा और मौसमी चारे जैसे लोबिया, मक्का, ज्वार, बाजरा, बरसीम आदि को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की जलवायु में लगभग 50 प्रकार के पशु चारे सहज रूप से उगाए जा सकते हैं, जिनमें एकदलीय और बहुदलीय दोनों प्रकार के चारे शामिल हैं। यही विविधता इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत बनेगी।

दीर्घकालिक समाधान, कम लागत

मोरिंगा पौधे लगभग 12–15 वर्षों और नेपियर घास 7–8 वर्षों तक लगातार हरा चारा उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। मोरिंगा न केवल उच्च प्रोटीन और खनिज तत्वों से भरपूर है, बल्कि गोशालाओं में प्राकृतिक छाया और जैविक फेंसिंग का भी काम करेगा। वहीं नेपियर घास अपनी उच्च उत्पादन क्षमता और नियमित कटिंग के कारण सतत चारा स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है।

हर गोवंश को पर्याप्त हरा चारा

योजना के अनुसार गोशालाओं में संरक्षित प्रत्येक गोवंश को पर्याप्त हरा चारा प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाएगा। हरा चारा पोषण की दृष्टि से सूखे चारे की तुलना में अधिक लाभकारी है। इससे गोवंश के स्वास्थ्य तथा दुग्ध उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार होगा। साथ ही चारा उत्पादन में आत्मनिर्भरता से बाहरी निर्भरता घटेगी और गोशालाओं की संचालन लागत में कमी आएगी।

हरित आवरण बढ़ेगा, भूमि की उर्वरता सुधरेगी

श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में तैयार इस समग्र कार्ययोजना के केंद्र में गोवंश संरक्षण, पोषण सुरक्षा, प्राकृतिक खेती, पर्यावरण संतुलन और ग्रामीण–शहरी सहभागिता को रखा गया है। मिशन फॉडर के माध्यम से न केवल गोशालाओं का दीर्घकालिक संचालन मजबूत होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर हरित आवरण बढ़ेगा और भूमि की उर्वरता सुधरेगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी योजना

प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा। यह पहल आत्मनिर्भर गोशाला, प्राकृतिक खेती और सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उस विजन को जमीन पर उतारने की दिशा में निर्णायक कदम मानी जा रही है, जिसकी नींव योगी सरकार ने रखी है।

भारत पांच साल में अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदने में सक्षम, व्यापार समझौते पर बोले गोयल

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। गोयल ने बताया कि वर्तमान में भारत 300 अरब डॉलर का सामान अमेरिका से खरीद सकता है, जो अभी वह दुनिया के अन्य देशों से लेता है। उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते का पहला चरण अंतिम रूप दे दिया है। इसके तहत भारत अगले पांच साल में ऊर्जा उत्पाद, विमान और पार्ट्स, कीमती धातु, तकनीकी उत्पाद और कोकिंग कोयला अमेरिका से खरीदने का इरादा रखता है। किसानों की बढ़ेगी आय– गोयल किसानों की आय पर जोर देते हुए गोयल ने कहा कि अमेरिकी बाजार किसानों को अधिक मूल्य देगा और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि भारत–अमेरिका के व्यापार समझौतों से किसानों को नई निर्यात संभावनाएं मिलेंगी, जिससे उन्हें बेहतर दाम और लाभ मिलेगा। गोयल ने कहा कि आज भारत व्यापार समझौतों की बातचीत ताकत और आत्मविश्वास के साथ कर रहा है। उनका मानना है कि भारत भविष्य में 35 ट्रिलियन डॉलर का बाजार पेश कर सकता है, और यही हमारी सबसे बड़ी वार्ता ताकत है। गोयल ने यह बात

भारत–अमेरिका के बीच शुल्क समझौते के बाद पीटीआई वीडियो को दिए अपने पहले इंटरव्यू में कही। यह समझौता दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार समझौते की ओर पहला कदम माना जा रहा है। भारत बनेगा 30–25 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था– गोयल उन्होंने कहा कि आज हम 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन 2047 तक यह बढ़कर 30–35 ट्रिलियन डॉलर होगी, जब हम एक विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। यही भारत का आत्मविश्वास है। इस वृद्धि का अवसर हम अपने व्यापारिक साझेदारों को पेश कर रहे हैं। गोयल के अनुसार यह भविष्य की संभावनाओं को लेकर भारत की रणनीति और ताकत का परिचय है, जिससे देश के लिए नए निवेश और व्यापार के अवसर खुलेंगे। गोयल ने कहा कि भारत पहले ही कृषि और मत्स्य उत्पादों का 55 अरब डॉलर का निर्यात कर रहा है। यह समझौता किसानों को और अधिक निर्यात अवसर और बेहतर लाभ दिलाने में सहायक होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी बाजार में नए अवसर किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने में मदद करेंगे और कृषि क्षेत्र की समृद्धि बढ़ाएंगे। विमान, इंजन और स्पेयर पार्ट्स की मांग गोयल ने बताया कि भारत पहले ही विमानों और इंजन के लिए 50 अरब डॉलर के ऑर्डर दे चुका है।

मेरा भी ऐसा करने का इरादा है, अरिजीत के फैसले पर विशाल ददलानी ने कही बड़ी बात; लोगों को दी यह सलाह

एजेंसी

सिंगर अरिजीत सिंह ने हाल ही में एलान किया है कि वह प्लेबैक सिंगिंग छोड़ रहे हैं। इस पर कई कलाकारों ने प्रतिक्रिया दी है। इस कड़ी में अब नया नाम सिंगर विशाल ददलानी का जुड़ गया है। आइए जानते हैं उन्होंने अरिजीत सिंह के सिंगिंग छोड़ने के बारे में क्या कहा है? इस चीज से होना चाहिए प्यार विशाल ददलानी ने आगे कहा आखिर में, आपको अपने लिए जीना होता है। जहां तक अरिजीत की बात है, अपने लिए जियो, मेरे भाई। मैं उसके लिए बहुत खुश हूं। मेरा भी ऐसा ही करने का इरादा है। आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, खुश रहना चाहिए और अपने फैसले खुद लेने चाहिए। ददलानी की सलाह बर्नआउट के बारे में ददलानी ने कहा मुझे नहीं लगता कि बर्नआउट जैसी कोई चीज होती है। हम म्यूजिक नाम के एक समुद्र में रहते हैं। कभी आप यहां जाना चाहते हैं, कभी वहां। जब तक आप जो कर रहे हैं उसका आनंद ले रहे हैं, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी और चीज पर भी ध्यान दें। हवाई जहाज उड़ाएं, दौड़ें, ट्रेकिंग करें, तैरने जाएं। मुझे लगा मैं बेफिक्र लड़का हूं..., तलाक के अलावा इस चीज से जूझ रहे थे इमरान खान; किया इलाज अरिजीत ने किया था सिंगिंग छोड़ने का एलान अरिजीत सिंह ने पिछले महीने अचानक प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का एलान किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था श्हैलो, आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। इतने साल तक श्रोताओं के रूप में मुझे इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। मुझे यह एलान करते हुए खुशी हो रही है कि मैं अब से प्लेबैक वोकलिस्ट के रूप में कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा। मैं इसे अलविदा कह रहा हूं। यह एक शानदार सफर रहा।

तेजस्विन शंकर का शानदार प्रदर्शन, एशियाई इंडोर चौंपियनशिप में पहले दिन शीर्ष पर

एजेंसी

नई दिल्ली। एशियाई खेलों के पदक विजेता और राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक तेजस्विन शंकर ने शनिवार को 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चौंपियनशिप में हेप्टाथलॉन स्पर्धा के पहले दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान के साथ अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। चार स्पर्धाओं के बाद 27 साल का यह खिलाड़ी कुल 3513 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है। चीन के जिहुई हुआ 3241 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। तेजस्विन डेकाथलॉन के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक भी हैं। उन्होंने दिन की शुरुआत 60 मीटर दौड़ में 7.11 सेकेंड का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय निकालते हुए 844 अंक हासिल किए। उन्होंने 7. 53 मीटर की छलांग के साथ लंबी कूद स्पर्धा से 942 अंक जोड़े। इसके बाद गोला फेंक में 13.63 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास से उन्हें 706 अंक मिले। दिन की चौथी और अंतिम स्पर्धा ऊंची कूद में तेजस्विन ने 2.23 मीटर का सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 1021 अंक हासिल कर तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए। हेप्टाथलॉन की शेष तीन स्पर्धाएं (60 मीटर बाधा दौड़, पोल वॉल्ट और 1000 मीटर) रविवार को अंतिम दिन आयोजित होंगी। महिलाओं की 60 मीटर दौड़ में भारत की नित्या गांधी ने 7.49 सेकेंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ सातवां स्थान हासिल किया।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743